भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2209
जिसका उत्तर मंगलवार 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

घरेलू मांग को सीमित करने वाले कारक

2209. **श्री विष्णु दयाल राम:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी प्रापण नीतियों में घरेलू मूल्य संवर्धन की ओर नकारात्मक दृष्टिकोण, संविदा की सख्त शर्तें, निरंतर आयात, पुरानी मशीनरी के उपयोग, उन्हें प्रतिस्थापित करने हेतु कोई प्रोत्साहन प्रदान न करना, 'आयात योजना' के अंतर्गत शुन्य आयात शुल्क और परियोजना कार्यान्वयन में विलंब घरेलू मांग को सीमित करने के प्रमुख कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थिति को सुधरने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): नेशनल केपिटल गुड्स पॉलिसी 2016 ने सरकारी प्रापण नीतियों में घरेलू मूल्य संवर्धन की ओर सकारात्मक पक्ष की कमी, कठिन संविदा शर्तों, सतत आयात और प्रतिस्थापन हेतु प्रोत्साहन के बिना पुरानी मशीनरी का उपयोग, 'परियोजना आयात' के अंतर्गत शून्य आयात शुल्क और परियोजना कार्यान्वयन में विलम्ब जैसे उन मुद्दों की पहचान की जो केपिटल गुड्स की घरेलू मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

(ख): फरवरी, 2017 में वित्त मंत्रालय ने सरकारी ई-बाजार स्थल, लाइफ साइकल लागत, उल्टी बोली और स्थानीय रूप से निर्मित सामानों की खरीद को प्राथमिकता जैसे तत्वों को आरंभ करके घरेलू विनिर्माताओं द्वारा प्रापण को बढ़ावा देने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों को संशोधित किया है।

दिनांक 15 जून, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए खरीद की प्राथमिकता की आवश्यकता न्यूनतम स्थानीय कन्टेन्ट अग्रिम में विशेष उल्लेख की आवश्यकता लाइसेंस के तहत न्यूनतम स्थानीय कन्टेन्ट और विनिर्माण में बढ़ोत्तरी, चरणबद्ध स्वदेशीकरण के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करार जैसे उपायों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल पर सरकारी खरीद के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकारी खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है।

इस आदेश की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने सरकारी खरीद के लिए केपिटल गुड्स और ऑटोमोटिव क्षेत्र की कुछ मदों के लिए स्थानीयकरण की आवश्यकता हेतु आदेश जारी किया है।

रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2016 से अपनी प्रापण प्रक्रिया को संशोधित किया जिसमें रक्षा खरीद में घरेलू विनिर्माताओं की भागीदार को सुगम बनाने का प्रावधान है।

******